इसके प्रभावों का अनुमान लगाना ऐसी स्थिति में असामयिक होगा ।

(ग) और (घ) परियोजना के लिए जुलाई, 1989 में दी गई निवेश संबंधी स्वीकृति के अनुसार, अक्टूबर, 1988 की विनिमय दर पर प्रति मेगावट उत्पादन लागत 3.24 करोड रु० आंकी गई है । लागत में वृद्धि मुख्यत विनिमय दर में भिन्नता के कारण हुई है । परियोजना की संशोधित लागत अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है । संसाधनों संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना को बाहरी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है । वर्तमान ठेके के अंतर्गत परियोजना को पूरा किए जाने से एन. एच. पी सी अपने निवेश पर जल्दी ही लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा ।

(ड.) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

तेन्दूघाट परियोजना की निर्माण लागत में वृद्धि

4328. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठ मलानी

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्टूबर, 1992 के "दि आबजर्वर" में 'पावर प्रोजेक्ट कास्ट एस्कलेटड 349 परसंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तेन्दूघाट ताप विद्युत परियोजना की लागत 349 प्रतिशत बढ गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) परियोजना को योजना आयोग द्वारा 175.13 करोड रु० की अनुमानित लागत पर मार्च, 1979 में स्वीकृत किया गया था । तेन्दुघाट विद्युत निगम लिमिटेड जोकि परियोजना को राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने हेतु परियोजना प्राधिकारी हैं, द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, परियोजना पर 835 करोड रु. की लागत आने का अनुमान है ।

(घ) और (ड.) माल-सामग्री, उपस्कर तथा श्रम संबंधी लागत में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है । 210 मे.वा के प्रथम यूनिट को जून, 1993 में तथा द्वितीय यूनिट को दिसम्बर, 1993 में चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुशलता बढ़ाकर विद्युत के बारे में बचत-लक्ष्य

4329. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या **विद्युत** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक कुशलता पैदा कर ऊर्जा बचत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य के अंतर्गत कितनी विद्युत की बचत होने की संभावना है ;

(ग) सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) इन कदमों के परिणामस्वरूप आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत

में पारगम्यता और वितरण हानि की मात्रा तथा संयंत्र उद्भार गुणक (प्लांट-लोड-फैक्टर) का प्रतिशत क्या होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 8वीं योजना के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 8वीं योजना के अंतिम वर्ष तक विद्युत की प्रतिष्ठापित क्षमता में 5000 मेवाट्ट की बचत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तयार की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी किया जाना और विद्युत उत्पादन यूनिटों के संयंत्र भार गुणक में सुधार किया जाना शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

Faulty electricity bills of DESU

4330. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that DESU is habitual of sending tlectricity bills to the consumers without taking actual meter reading;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to ensure that no consumtr gets electricity bill without actual meter reading for the quantum of electricity consumed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) Bills to the domestic consumers with sanctioned load of less than 11 KW are issued by DESU on an actual reading basis once in four months. In between, a bi-monthly bill is issued on a provisional basis. In other categories, the bills are issued on a monthly basis. Every effort is made by DESU to issue the bills on actual reading basis as per the existing procedure. However, apart from the cases of "Locked Premises". and "Defective Meters", possibilities of some omissions in taking meter reading in a largt network comprising of about 18 lakh consumers, cannot be avoided.

Mou for setting up seven power plants in Karnataka

4331. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact during the recent visit abroad of the Chief Minister of Karnataka, an MOU was signed for attracting foreign investments of Rs. 6,000 crores, for setting up seven power projects with an overall capacity of 2838 MW in the State; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Details of MOUs signed by Government of Karnataka for power projects in the private/ joint sector are given below: